प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 23 – 30 अक्तूबर 2017 मूल्य पांच रूपए

भाजपा पर भारी पड़ सकती है वीरभद्र के भ्रष्टाचार पर अतिकेन्द्रियता

शिमला/शैल। भाजपा की प्रदेश से लेकर केन्द्र तक की सारी लीडरशीप इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर चल रही है। भाजपा के हर छोटे-बडे नेता की जनसभा और पत्रकार वार्ताएं वीरभद्र के भ्रष्टाचार से शुरू हो रही है। लेकिन इसी के साथ यह भी कहते हैं कि वीरभद्र के खिलाफ उनकी सरकार में नही बनाये गये बल्कि यूपीए सरकार के समय से चले आ रहे है। परन्तु वीरभद्र इन मामलों को जेटली, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर का एक षडयंत्र करार देते रहे है। इस षडयंत्र के लिये वह तर्क देते हैं कि यूपीए शासनकाल में सीबीआई ने जो प्रारम्भिक जांच की थी उसमें उन्हे क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन भाजपा सरकार ने इस क्लीन चिट को नजर अन्दाज करके उनके खिलाफ नये सिरे से जांच करवाई की। जिसके परिणामस्वरूप यह मामले खड़े हुए हैं। इस परिदृश्य में यदि वीरभद्र के मामले की पड़ताल की जाये तो यह सामने आता है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला खड़ा किया है। सीबीआई इस मामले में अपनी जांच पूरी करके चालान ट्रायल कोर्ट में डाल चुकी है। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की गुहार वीरभद्र सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर चुके हैं परन्तु दोनों अदालतें उनके आग्रह को अस्वीकार कर चुकी है। सीबीआई द्वारा बनाये गये आय से अधिक मामले को ईडी मनीलाड्रिंग मानकर जांच कर रही है। मनीलॉड्रिंग प्रकरण में ईडी दो अैटचमैन्ट आदेश जारी करके परिवार की चल-अचल संपत्ति को अैटच कर चुकी है। इस मामले में पहले अटैचमैन्ट आदेश के बाद ईडी वीरभद्र के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को गिरफ्तार कर चुकी है। आनन्द चौहान जून 2016 से हिरासत में है। आनन्द की गिरफ्तारी पहले जारी हुए अटैचमैन्ट आर्डर में ईडी ने कहा कि इस मामले में वक्कामुल्ला को लेकर अभी जांच पूरी नही हुई और इसे शीघ्र ही पूरी करके अनुपूरक चालान दायर किया जायेगा। यह वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के प्रसंग को लेकर ईडी अभी तक अपनी शेष जांच पूरी नही कर सका है। इसी कारण से अनुपूरक चालान दायर नही हो पाया है और कोई गिरफ्तारी भी नही हो पायी है। लेकिन इसी के कारण आनन्द चौहान के चालान पर भी आगे कारवाई नही बढ़ पायी है। ईडी में दर्ज मामले को भी रद्द करवाने की गुहार वीरभद्र सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय से लगा चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय इस गुहार को अस्वीकार करके ईडी को हर तरह की कारवाई के लिये स्वतन्त्र कर चुका है। लेकिन ईडी की ओर से अगली कारवाई नही की जा रही है। ईडी के इस आचरण पर केन्द्रिय मन्त्री अरूण जेटली और रविशंकर प्रसाद तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा तक कुछ नहीं कह पाये हैं।

यही नहीं वीरभद्र सिंह के प्रधान निजि सचिव और सरकार के मीडिया सलाहकार सुभाष आहलूवालिया के मामले में शिमला स्थित ईडी कार्यालय ने उनको नोटिस जारी करके तलब किया था। तब शिमला मे तैनात ईडी के सहायक निदेशक का वीरभद्र सरकार ने अचानक उनका डैपुटेशन कैन्सिल करने की कारवाई शुरू कर दी थी और अन्त में उस सहायक निदेशक को हिमाचल पुलिस में वापिस आना पड़ा था। उस समय भाजपा ने सहायक निदेशक को सरकार द्वारा वापिस बुलाये जाने के मामले पर भाजपा ने प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। तीन दिन तक सदन की कारवाई को बाधित रखा था। आहलूवालिया के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत ईडी के पास पहुंची हुई थी। करीब सौ करोड़ की मनीलॉड्रिंग के आरोप उस शिकायत मे थे, लेकिन ईडी के किसी भी नोटिस पर आहलूवालिया के ऐजैन्सी में पहुंचने की खबर नही है। उस शिकायत पर ईडी में क्या कारवाई हुई इसकी आज तक किसी को जानकारी नही है। लेकिन इस मुद्दे पर सदन को तीन दिन तक बाधित रखने वाली प्रदेश भाजपा और ईडी भी आज तक एकदम चुप है। जो भाजपा वीरभद्र के मामले को हर रोज मुद्दा बनाकर उछाल रही है। वह आज आहलूवालिया के मामले पर चुप क्यों है। भाजपा की चुप्पी से ज्यादा तो ईडी की खामोशी सवालों में है। बल्कि अब तो यह चर्चा उठती जा रही है कि हिमाचल की एचपीसीए को लेकर जो आपराधिक मामले प्रदेश भाजपा नेताओं के खिलाफ आज अदालत तक पहुंच चुके है और इन नेताओं को भी जमानते लेनी पड़ी है उसमें एक मामलें में आहलूवालिया समेत वीरभद्र कार्यालय के दो अधिकारी भी चालान में खाना 12 में बतौर अभियुक्त नामतद है। चर्चा है कि इनके खाना 12 में बतौर अभियुक्त नामज़द होने के कारण ही एचपीसीए के खिलाफ चल रहे मामले आगे नही बढे हैं और बदले में ईडी इनके मामलों में चुप होकर बैठी है।

स्मरणीय है कि सीबी आई के दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ जांच चल रही है एक निदेशक के खिलाफ तो यह आरोप है कि उसे ई डी हिरासत में चल रहे मीट विक्रेता मोईन कुरैशी के माध्यम से कुछ लोगों के मामलों को दबाने के लिये करोड़ो की रिश्वत मिली है। मोईन कुरैशी के प्रदेश के किन लोगों के साथ क्या रिश्ते हैं इसे बहुत लोग जानते हैं। इसीलिये जब वीरभद्र सिंह और सुभाष आहलूवालिया के मामले में ईडी तो चुप बैठी हुई है। भाजपा आहलूवालिया के मामले को नजरअन्दाज कर रही है और वीरभद्र के मामले को हर रोज मुद्दा बना रही है तो यह स्वभाविक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा हैं वैसे तो भाजपा के लिये एक परेशानी वाला यह सवाल भी खड़ा है कि जहां वीरभद्र ज़मानत पर हैं वहीं पर धूमल, अनुराग, राजीव बिन्दल और वीरेन्द्र कश्यप आदि भाजपा के नेता भी ज़मानत पर हैं। इस परिदृश्य में भाजपा द्वारा वीरभद्र के मामले को रोज उठाना जबकि ईडी एकदम शान्त बैठी है इससे स्वभाविक रूप से यह संकेत उभरता है कि भाजपा केन्द्र की एजैन्सीयों के नाम से अपने राजनीतिक विरोधीयों को भ्रष्टाचारी प्रचारित करके राजनीतिक ब्लैकमेलिंग कर रही है। क्योंकि सीबीआई का चालान तो ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुका है। और उसका फैसला आने में लम्बा समय लगेगा। फैसले से पहले ही इसमे फतवा देना शुद्ध राजनीति है। ईडी की तो अभी जांच भी पूरी नही हुई है यह ईडी ने आनन्द चौहान की गिरफ्तारी में स्वयं स्वीकार किया है। बल्कि इसके बाद ही चर्चा उठी थी कि ईडी वीरभद्र के खिलाफ कोई ठोस मामला बना नही पा रही है। उल्टे ईडी की फज़ीहत हो रही है कि सहअभियुक्त तो जेल में है और मुख्यअभियुक्त बाहर है। ईडी वित्त मन्त्रालय के अधीन है। और इसीलिये वित्त मन्त्री अरूण जेटली एक कानूनविद होने के बावजूद इस संद्धर्भ में पूछे गये सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नही दे पाये हैं।

एक बड़ा सवाल

ई डी में अभी जांच पूरी नहीं हुई है

नौणी विवि में संयंत्र रोग प्रबंधन में जैव –तर्कसंगत दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

हमीरपुर/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में संयंत्र रोग प्रबंधन में जैव-तर्कसंगत दृष्टिकोण(Bio-rational Approaches in Plant Diseases Management) विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग द्वारा भारतीय सोसाइटी ऑफ प्लांट

पैथोलॉजिस्ट और हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वावधान में किया जा रहा है।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक (बागवानी) डा. ए. के.सिंह मुख्य अतिथि रहे। डा. पी.के. चक्रवर्ती, ए.डी.जी. (आईसीएआर) गेस्ट ऑफ ऑनर और नौणी विवि के उप कुलपति डा. एचसी शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आजादी के बाद देश को अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हुए डा. सिंह ने कहा कि विकास की वर्तमान दर पर, अनाज का उत्पादन एक बड़ी समस्या नहीं होगा लेकिन गुणवत्ता उत्पादन और पौधों का संरक्षण के मुद्दे एहम रहेगें। उन्होंने वैज्ञानिकों से सभी हितधारकों की शिक्षा में सुधार लाने और सर्वोत्तम तकनीकों का समय पर प्रसार की दिशा में काम करने के लिए कहा।

अपने संबोधन में डा.पी.के. चक्रवर्ती ने देश में खाद्य उत्पादन के नुकसान से संबंधित तथ्यों को साझा किया। उन्होंने बताया कि संभावित खाद्य उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक, कीट और बीमारियों के कारण नष्ट हो जाता है। अगर हम इस समस्या से निपटने में सक्षम हो जाएं तो हम अपने मौजूदा उत्पादन में 70 लाख टन तक की वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे 'कीटनाशक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी' और खेती की जैव सुरक्षा की तरफ भी काम करें।

इस मौके पर डा. एच.सी. शर्मा ने कहा कि जलवायु परिस्थितियों और फसल के पैटर्न में बदलाव, इस क्षेत्र के लिए नई चुनौतियों लाएगा जिन्हें हमें सही ढंग से समझना होगा। उन्होंने कहा कि रोगजनकों और मेजबान पौधों पर उनका परस्पर प्रभाव को भी समझने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

इस अवसर पर सारणियों की पुस्तक भी जारी की गई। मुख्य अतिथि ने नौणी विवि के वैज्ञानिक डा. एस.के. गुप्ता और डा. एच.आर.गौतम द्वारा फसल रोगों पर लिखी पुस्तक का भी विमोचन किया। हिमालयन फाएटोपथोलोजिकल सोसाइटी ने दुनिया भर में पौध रोग विज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध डा. सुरेश पांडे और डा. टीएस थिंड को सम्मानित किया।

यहां देश के विभिन्न हिस्सों के लगभग 150 वैज्ञानिक और छात्र बीमारी प्रबंधन के पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विचार-विमर्श और अंतिम उपयोगकर्ता के प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेगें। इस कार्यक्रम के जरिए किसानों, वैज्ञानिकों और निजी उद्यमियों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न किया गया है।

पादप-रोग उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक हैं, जिनका वैश्विक कृषि उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन इस स्थिति को और भी बढ़ा सकता है। पिछले 40 सालों में, खाद्य उत्पादन बढ़ाने में बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी रोगजनक (Pathogens) वैश्विक फसल का बड़ा हिस्सा खराब कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक समस्याएं और कीटों की उभरती चुनौतियों ने मिलकर पौधे स्वास्थ्य प्रबंधन को और अधिक जटिल कार्य बना दिया है।

देश की दशा व दिशा बदल सकते है युवा:राज्यपाल

शिमला/शैल। श्री रामानंद निर्मला देवी सूद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मंडी जिले के करसोग में आयोजित अंतर विद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि युवाओं के चरित्र निर्माण से देश का निर्माण संभव है, क्योंकि युवा ही देश की दिशा व दशा बदल सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और देश को इन युवाओं से काफी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने युवा शक्ति के चरित्र निर्माण पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक व उच्च शिक्षा के साथ-साथ भावी पीढ़ी में संस्कार, नैतिक मूल्य और राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। इसके लिए, भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी जानी चाहिए तथा उन्हें महापुरूषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कौम व समाज तभी जीवित रहता है जब वह अपने महापुरूषों के इतिहास व उनके बलिदान को याद रखता है।

आचार्य देवव्रत ने युवाओं से आग्रह किया कि वे माता-पिता व गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखें और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति आध्यात्मवाद की रही है। इस देश ने दुनिया को प्रेम, शांति, सौहार्द, सहिष्णुता, उच्च परम्पराएं, चरित्र निर्माण, संस्कृति व समरसता का पाठ पढ़ाया है। भोगवादी संस्कृति से दूर हमने आध्यात्मवादी व परोपकारी संस्कृति का प्रचार किया। वेदों के माध्यम से दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। अपनी संस्कृति पर युवा पीढ़ी को गर्व होना चाहिए।

उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे जहां क्षेत्र के युवा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे वहीं उनमें समाज सेवा का जज्बा भी पैदा होगा। इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में 23 स्कूलों के लगभग 1300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि वाद-विवाद प्रतियोगिता, समूह गान, कविता पाठ इत्यादि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था। उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बरोवालिया, पूर्व न्यायाधीश टी.एस. राणा, पूर्व न्यायाधीश कुलदीप सिंह तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

माफिया सरगना ने चलाई कांग्रेस सरकार :अरुण धूमल

हमीरपुर/शैल। सुजानपुर विधानसभा में दर्जन भर गाँवों में भाजपा युवा नेता अरुण धूमल नेप्रचार अभियान चलाते हुए कई जगह नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित किया तो कई जगह डोर टू डोर अभियान भी चलाया। सुजानपुर के निहारी, सरगुण, भोग, खैरढ़, खिड़की, बलेयु, बाड़ी, लोंगणी और करोत खास इत्यादि सहित सुजानपुर शहर में अरुण धूमल के हुए चुनावी कार्यक्रमों में, इन क्षेत्रों की जनता की आँखों में इस बात की खुशी साफ झलकी कि उनके क्षेत्र से पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे है।

बहरहाल भाजपा नेता अरुण धूमल ने चुनावी सभाओं में लगातार कांग्रेस के गत पांच वर्षों की असफलताओं का कच्चा चिटठा और किये भ्रष्टाचार की पोल खोलने का अभियान जारी रखा हुआ है। अरुण धूमल चुनाव सभाओं में मुख्यमंत्री पर भी तीखा हमला कर रहे है। बकौल अरुण धूमल प्रदेश में रही कांग्रेस की सरकार को मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि माफिया राज के मुख्य सरगना ने चलाया है। प्रदेश की छवि को धूमिल करते हुए इन पांच वर्षो में शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, ट्रान्सफर माफिया, वन माफिया और सबसे बड़े स्तर पर नशा माफिया खूब फला फूला है।

उन्होंने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाते हुए कहा की आज की युवा पीढ़ी को इस नशा माफिया से बचाना जरुरी है। उन्होंने कहा कि यही नशे की लत आगे चल कर कोटखाई प्रकरण जैसे असहनीय घाव समाज को देते हैं। स्थानीय लोगों का आहवान करते हुए उन्होंने कहा की क्षेत्र के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए तैयार हो जाएँ और नशे जैसी बुराई की जड़ को उखाड़ फैंके। उन्होंने कहा की सुजानपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।

अरुण धूमल ने सुजानपुर की जनता से कहा की वह कांग्रेस से पिछले पांच वर्षो का हिसाब मांगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गत पांच वर्षो में हमीरपुर जिला से जो भेदभाव किया है उसका जवाब कांग्रेस से मांगे। जिस कांग्रेस की सरकार ने हमीरपुर से भेदभाव के चलते कई दफ्तर बदल दिए वह क्या मुंह लेकर चुनावों में हमीरपुर की जनता से वोट मांगेगी। हालांकि केंद्र ने हजारों करोड़ रूपए प्रदेश को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिए हैं लेकिन केवल इसी डर से की इन योजनाओं के धरातल पर लागू होने से केंद्र की भाजपा सरकार को लोकप्रियता न मिले, प्रदेश की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने इन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप प्रदेश को लोगों को इन योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा है। प्रदेश की जनता को मौका मिला है वह कांग्रेस से पांच वर्षो का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा की जनता कांग्रेस के धोखे में नहीं आने का मन बना लिया है और भाजपा का सिक्टी प्लस होकर रहेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

7वें वेतन आयोग की वेतन सिफारिशें एवं एक समान पैन्शन सुविधा की मांग

शिमला/शैल। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के कर्मीयों पर लागू न होने को लेकर कर्मचारी नेता केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरूण जेटली के शिमला आगमन पर पीटर ऑफ में मिलें तथा वित्त मन्त्री को कर्मचारी नेता विनोद कुमार एवं शिक्षक नेता डा.एम.आर. पुण्डीर ने प्रतिपक्ष नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री प्रो.प्रेम कुमार धूमल और केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डा की उपस्थिति में 7वें वेतन आयोग की वेतन सिफारिशें एवं एक समान पैन्शन सुविधा और उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर प्रदेश की जन-जातीय क्षेत्रों में आयकर में विशेष छूट सुविधा को प्रदेश में नई सरकार के गठन पर लागू करने का मांग-पत्र सौंपा तथा वित्त मन्त्री से प्रदेश की माली वित्तीय हालात को देखते हुए इन सिफारिशों के लागू करने को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदेश को देने की मांग की गई।

वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने कर्मी नेताओं की मांग पर हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या अभी तक प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है। इस पर वित्त मन्त्री को अवगत करवाया गया कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार, फजूलखर्ची और वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते प्रदेश लगभग 45000 करोड़ रूपये के कर्जे में दबा है और ऐसी विक्ट आर्थिक परिस्थितियां आने वाली सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है । वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने आश्वस्त किया कि नई सरकार के आने पर हिमाचल प्रदेश के कर्मीयों को 7वें वेतन आयोग को बिना किसी देरी के लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। कर्मी नेताओं ने वित्त मन्त्री को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश एक कर्मचारी बहुल क्षेत्र है यहां लगभग छः लाख परिवार कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध रखते हैं और इनके साथ-साथ प्रदेश के अन्य वर्गो के हित भी जुड़े हुए होते हैं जबकि वर्तमान में वेतन-आयोग की सिफारिशें लागू न होने की बजह से प्रदेश के कर्मचारियों को कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 तक का प्रति माह आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वित्त मन्त्री के इस आश्वासन का कर्मचारी नेताओं ने उनका आभार प्रकट किया है कि प्रदेश के कर्मीयों को पूर्ण आशा है कि नई सरकार के गठन के बाद केन्द्रीय वित्तीय सहायता से प्रदेश के कर्मीयों को नया वेतन आयोग लागू हो सकेगा।

देश में खत्म हो रही मोदी लहर:हरीश रावत

शिमला/शैल। उतराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नोटबंदी और जीएसटी के निर्णयों को लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार

की आलोचना की है। रावत ने इन फैसलों को अलोकतात्रिक करार देते हुए कहा कि इनसे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और आम जनता पर इनका खास असर पड़ा है।

शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि अब देश में मोदी लहर खत्म हो रही है और हिमाचल व गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी मात मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उतराखण्ड में भाजपा को मोदी लहर के साथ-साथ ईवीएम के मैजिक से एकतरफा जीत मिली थी। लेकिन अब मोदी और ईवीएम मैजिक काम करने वाली नहीं हैं, क्योंकि देश की जनता को विश्वास हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। रावत ने कहा कि ईवीएम में वीवीपैट के प्रयोग से अब गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो गई है।

उन्होंने मंहगाई के मद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। पूर्व यूपीए सरकार के समय मंहगाई उस समय बढ़ी थी, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 121 बैरल प्रति लीटर पहुंची थीं। जबकि मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमत 40 से 49 बैरल प्रति लीटर होने के बावजूद मंहगाई अनियंत्रित हो गई है।

उन्होंने मोदी सरकार पर हिमालयन राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि इन राज्यों के विशेष दर्जे की श्रेणी को छीनकर कुठाराघात किया गया है।

रावत ने कहा कि हिमाचल में बीते पांच साल में अथाह विकास हुआ है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल रोल मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आज सभी हिमालयन राज्यों को वीरभद्र सिंह जैसे अनुभवी व सशक्त नेतृत्व की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हिमालय प्रदेशों को यदि अनुभवी व सशक्त नेतृत्व नहीं मिलेगा, तो इनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी।

रावत ने कहा कि वीरभद्र सिंह अपने आप में बड़ा चेहरा हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वीरभद्र सिंह की आलोचना करने के लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। वीरभद्र की अगुवाई में हिमाचल में इतने विकास कार्य हुए हैं कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा है, जिससे वे वीरभद्र के खिलाफ हमला बोल सकें। उतराखंड की पिछली कांग्रेस सरकार ने कई मामलों में वीरभद्र सरकार का अनुकरण किया था।

कांग्रेस पार्टी द्वारा एक परिवार एक टिकट की नीति को दरकिनार कर हिमाचल में टिकट बांटने को जायज ठहराते हुए रावत ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों को एक परिवार से टिकट दिए गए हैं, वे कांग्रेस पार्टी में कई सालों से सक्रिय हैं।

भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग का हितैशी:थावर चंद गहलोत

शिमला/शैल। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सवैंधानिक दर्जा दिलाने में अड़ंगा डालने का ठिकरा कांग्रेस पार्टी समेत प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के दो राज्यसभा सदस्यों आनंद शर्मा और विपल्व

ठाकुर पर फोड़ते हुए मोदी सरकार में सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने भाजपा सरकार को पिछड़ा वर्ग का हितैशी होने का दावा किया है।

हिमाचल में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की खातिर प्रचार के लिए शिमला पहुंचे गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल लाया। जिसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने उस बिल को पास कराने में अड़ंगा डाल दिया और इस मुहिम में राज्य सभा में उपनेता व हिमाचल से राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा व विपल्व ठाकुर ने भी अड़ंगा डाला। विपल्व ठाकुर कांगड़ा जिला से कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रही हैं।

उन्होंने इन चुनावों में दलित कार्ड चलने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सभी के विकास में भरोसा करती हैं। आरक्षण के मुद्दे पर वो बोले की जब तक समाज में विषमता रहेगी भाजपा आरक्षण के पक्ष में रहेगी। याद रहे बीजेपी के एक धड़े व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर बीजेपी को संकट में डाल दिया था। ऐसे में पार्टी अब इस मसले पर संभलते हुए चल रही हैं।

उन्होंने संविधान निर्माता भीम राव अंबेदकर से जुड़ी विरासत को विसतार देने के लिए मोदी सरकार की ओर से बहुत कुछ किया जा रहा है।

सोनिया गांधी की बेहद करीबी विद्या स्टोक्स का नामांकन रद्द

शिमला/शैल। सोनिया गांधी की बेहद करीबी व वीरभद्र सिंह सरकार में वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स

का ठियोग विधानसभा हलके से नामांकन रदद होने के मामले ने कांग्रेस आलाकमान व पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया हैं। छंटनी के रोज रिटर्निंग अफसर टी एस नेगी ने उनके नामांकन को रदद कर दिया। इससे पहले सुबह इस मसले को तीन बजे तक स्थगित कर दिया गया। उसके बाद पांच बजे तक फैसले के लिए समय दिया गया। पांच बजे फैसला आ गया व उनका नामांकन रदद कर दिया गया। अब ठियोग से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के करीबी व बिल्कुल नया चेहरा दीपक राठौर होंगे।

वीरभद्र सिंह के ठियोग के बजाय अर्की से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस आलाकमान से दीपक राठौर ही अपने लिए टिकट लाए थे। उन्होंने अपना नामाकंन भी भर दिया। लेकिन विद्या स्टोकस ने पर्चा भरने के आखिरी दिन बीते रोज लंच के बाद आनन फानन में नामाकंन भरा। ऐसे में गलती रह गई। उनके पास कांग्रेस आलाकमान से अधिकार पत्र भी नहीं था। ये अधिकर पत्र प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने दिया था। रिटर्निंग अफसर ने इसे खामी पाया और उनके नामांकन को रदद कर दिया।

89 साल की विद्या स्टोक्स ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए ठियोग सीट छोड़ दी थी । लेकिन वीरभद्र सिंह ने ऐन मौके पर पैंतरा बदला दिया और वो ठियोग से सरक करअर्की चले गए।

ऐसे में कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान हो गया व दीपक राठौर ने आला कमान से जुगाड़ कर अपने लिए टिकट हथिया लिया। जबकि वीरभद्र सिंह व विद्या स्टोकस ने विजय पाल खाची को टिकट देने की वकालत की थी। उनका टिकट नहीं बदला गया लेकिन आलाकमान ने कहा कि अगर स्टोक्स लड़ना चाहती हैं ता उन्हें टिकट दिया जाता हैं। लेकिन आलाकमान से जरूरी कागजात शाम छह बजे तक समय पर नहीं पहुंचे व उनका नामांकन रदद हो गया। विद्या स्टोक्स आठ बार विधायक रह चुकी हैं।

अब बड़ा सवाल ये है कि आलाकमान से अधिकार पत्र समय पर क्यों नहीं पहुंच पाया। क्या कोई साजिश हुई हैं या आलाकमान ने स्टोक्स से दगाबाजी कर दी। यहां ये गौरतलब है कि विद्या स्टोक्स व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच सालों से छतीस का आंकड़ा रहा है।

अब ठियोग विधानसभा हलके में भाजपा प्रत्याशी राकेश वर्मा व वामपंथी माकपा प्रत्याशी राकेश के बीच मुकाबला है। कांग्रेस को यहां से हारा हुआ माना जा रहा है।

धर्मवीर धामी का कांग्रेस से निष्कासन रद्द

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाली के कदावर नेता धर्मवीर धामी का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। उनकी पार्टी में वापसी से समर्थकों में खुशी का माहौल है। धामी ने साल 2012 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था,इसके बाद कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए धामी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की सिफारिश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने धामी के निष्कासन को रद्द करते हुये उन्हें कांग्रेस पार्टी में वापस लेने के आदेश जारी किये है।

धर्मवीर धामी काफी समय स पार्टी से जुड़े हुए थे तथा इनके निष्कासन की बहाली करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा की उन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में जताई है तथा वे पहले की भान्ति अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिये कार्य करते रहेंगे।

रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बजाए दोषारोपण का सहारा ले रहे वीरभद्र सिंह:धूमल

हमीरपुर/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर में चुनाव अभियान के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुये कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह को क्षेत्रवाद और जातिवाद का आरोप लगाने का रोग लग गया है । अपने राजनैतिक जीवन में वह क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करते रहे। सेब उत्पादकों को यह कह कर गुमराह करते रहे कि भाजपा सेब उत्पादकों की विरोधी है और अगर सता में आयेगी तो उनके हितों को नुकसान पहुंचायेगी।

उन्होंने कहा कि जब 1998 में भाजपा सता में आई तो सेब उत्पादकों के लिये जो काम हमारी सरकार ने किया उससे सब के भ्रम टूट गये। दोनों बार की सरकार 1998 से 2003 तथा 2007 से 2012 के सर्वस्पर्शी अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुये नीतियां बनाई और काम किये परिणामस्वरूप आज उन क्षेत्रों के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबको जोड़ने वाली सबके हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी मानते हैं जबकि कांग्रेस सरकार तो बागवानों के बगीचों के लिये हमने जो सड़कें बनाई थी उनका रखरखाव भी नहीं कर सकी अर्थात अब सेब उत्पादक क्षेत्र में भी मोदी सरकार के कारण, उनकी नीतियों के कारण और प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा सेब उत्पादकों के हित में किये गये काम के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है । मुख्यमन्त्री तो अपने ही चुनाव क्षेत्र में घिर गये हैं।

प्रो. धूमल ने कहा जहां तक जातिवादी राजनीति की बात है इतना ही प्रमाण काफी है, जब मण्डी संसदीय क्षेत्र से मुख्यमन्त्री की धर्मपत्नी संसद का चुनाव हारीं तो उन्होंने यह कह दिया कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के ब्राहमणों ने मिलकर मुख्यमन्त्री की धर्मपत्नी को हरा दिया। इस ब्यान से उनकी मानसिकता झलकती है और प्रदेश की जनता जानती है कि जातिवाद की राजनीति कौन करता है? इस बार पांच साल सता में रहने के बाद उनको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनता के समक्ष रखने की अपेक्षा दूसरों पर दोषारोपण करने का सहारा लेना पड़ रहा है, यह बड़ी विचित्र बात है। लगता है कि उनको भी महसूस होता होगा, इस कार्यकाल में खोखली घोषणाओं के सिवाये उन्होंने कुछ नहीं किया । शिमला में बैठकर 36-36 शिलान्यास कर दिये, बिना बजट व अन्य प्रावधानों के, इसलिये मुख्यमन्त्री जनता का ध्यान भटकाने के लिये निरर्थक ब्यानवाजी कर रहे हैं।

कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार में हरियाणा के नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियां सौंपी

शिमला/शैल।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी 9 नवम्बर को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को प्रमुखता देते हुए उन्हें पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियां सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा जारी पर्यवेक्षकों की सूची में प्रदेशभर से 20 नेताओं की हिमाचल प्रदेश में ड्यूटीयां लगाई हैं। इन पर्यवेक्षकों में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला को नालागढ़ विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी दी गई है।अशोक बुवानीवाला पहले भी उत्तराखंड विधानसभा एवं दिल्ली एमसीडी चुनावों में पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं तथा अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को जीताने में अहम भूमिका निभा चुके है। बुवानीवाला प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री के मीडिया कोर्डिनेटर तथा प्रदेश प्रवक्ता के पद की जिम्मेवारी भी संभाल चुके हैं। छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के कारण पार्टी की नीतियों एवं उनके प्रचार-प्रसार का वह अच्छा खासा अनुभव रखते हैं तथा राजनीति के साथ-साथ वैश्य समाज के सर्वोच्च नेता के रूप में संगठन में काम करने का अनुभव उन्हें प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास एवं उनकी कार्यनिपुणता से प्रभावित होकर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विश्वास जताते हुए उन्हें यह जिम्मेवारी दी है। बुवानीवाला के अलावा प्रदेश कांग्रेस से लखन सिंगला फरीदाबाद, मनदीप चटा पिहोवा, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवीनगर, पूर्व विधायक भारत भूषण बत्तरा रोहतक, संजय छोक्कर समालखां, पूर्व मंत्री सत्यनारायण लाठर जुलाना, पूर्व मंत्री बिजेन्द्र सिंह कादयान पानीपत ग्रामीण, पवन गर्ग लाडवा, पूर्व मंत्री आफताब अहमद नूहं, पूर्व विधायक सतविंदर राणा कालका, पूर्व विधायक जसबीर मल्लौर अम्बाला, पूर्व मंत्री बीएल सैणी जगाधरी, श्याम सुंदर बत्तरा यमुनानगर, कवि राज शर्मा, जाकिर हुसैन यमुनानगर, पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी पलवल, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता लाडवा, वरूण मुलाना, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जगाधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

आलसी राजा अपने विवेक की रक्षा नहीं कर सकता।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या नोटबंदी चुनाव पर असर डालेगी?

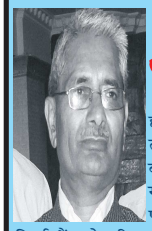

प्रदेश विधानसभा के लिये 9 नवम्बर को मतदान होने जा रहा है और 8 नवम्बर को नोटबंदी के फैसले को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो रहा है। विपक्ष ने 8 नवम्बर का ब्लैक डे तो सत्तापक्ष ने इसे कालेधन का प्रहार के रूप मे मनाने का फैसला लिया है। इस परिदृश्य में नोटबंदी के फैसले की समीक्षा किया जाना आवश्यक हो जाता है। रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है कि नोटबंदी के बाद 99% पुराने नोट उसके पास वापिस आ गये है और इसी के साथ यह भी स्वीकारा है कि इस फैसले के बाद जीडीपी में कमी आयी है। नोटबंदी के बाद ही ''एक देश एक टैक्स'' के तहत जीएसटी का फैसला लागू हुआ है। नोटबंदी के फैसले की समीक्षा करना, उस पर प्रतिक्रिया देना आम आदमी के लिये आसान नही है। लेकिन जीएसटी के फैसले से जिस कदर आम आदमी प्रभावित हुआ है उसका असर इसी से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के राजस्व सचिव आढ़िया ने एक ब्यान मे माना कि जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा से जब इस बारे में एक पत्रकार वार्ता में पूछा गया तो उन्होने जीएसअी लागू करने के लिये एनडीए सरकार की बजाये जीएसटी कांऊसिल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जबकि इसे लागू करते समय मोदी की एनडीए सरकार ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया था। जीएसटी पर जिस तरह मोदी सरकार जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों से हुए नुकसान और आम आदमी को मिली पेरशानी से अब मोदी सरकार बैकफुट पर आ गयी है।

इन फैसलों का अभी हिमाचल और गुजरात के चुनावों पर क्यों और क्या असर पड़ेगा। इसकी पड़ताल करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब यह फैसले लिये गये थे उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी? किसी देश की अर्थव्यवस्था में करंसी उस देश के जीडीपी के अनुपात में छापी जाती है। चीन हमारे से बड़ा देश है उसका जीडीपी दस लाख करोड़ अमेरीकी डॉलर है और हमारा दो लाख करोड़ अमेरीकी डॉलर है। चीन में करंसी 9% तथा भारत में 10:6 के अनुपात में छापी जाती है। रिजर्व बैंक इस सन्तुलन को बनाये रखता है। रिजर्व बैंक की साईट पर आये मनी स्टाक के आंकड़ो के मुताबिक जुलाई 2016 को 17,36,177 करोड़ की कुल करंसी परिचालन में थी। इसमें से 475034 करोड़ बैंको की तिजोरी में थी और 16,61,143 करोड़ बैंको के बाहर जनता के पास थी। लेकिन जनता के पास इतनी ज्यादा करंसी होने के वाबजूद जनता खरीददारी नही कर रही थी। बैकों के पास पैसा आ नही रहा था। बैंक भुगतान के संकट में आ गये थे ऊपर से सरकार और बैकों को मार्च 2019 तक ब्रेसल-3 के मानक परे करने थे। इसके लिये प्रोविज़निग की जानी थी जिसके लिये पांच लाख करोड़ की नकदी चाहिये थी। इस स्थिति को सरकार ने यह माना कि जब जनता इतनी करंसी होने के वाबजूद खरीददारी नही कर रही है तो निश्चित रूप से इतना पैसा लोगों के पास कालेधन के रूप में है। यह कुल करंसी का 86% था। इससे उबरने के लिये एक तरीका यह था कि जो कर्ज दिया गया है उसकी सख्ती से वसूली की जाए। लेकिन ज्यादा कर्ज बड़े उद्योगपतियों के पास था और सरकार उन पर सख्ती नही करना चाहती थी। इसलिये सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। सरकार को विश्वास था कि 500 और 1000 के नोटों का परिचालन बंद करके उसे नये सिरे से 86% करंसी छापने का अधिकार मिल जायेगा और पुराने नोट क्योंकि कालाधन है तो वह उसके पास वापिस नही आयेंगे। इस तरह नयी करंसी के सहारे वह बड़े घरानों के कर्ज भी माफ कर देगी और बैंक भी संकट से निकल जायेंगे। इसीलिये नोटबंदी की घोषणा के साथ ही यह कहा गया 2.5 लाख से ज्यादा जमा करवाने पर जांच की जायेगी। जब जनधन खातों में पैसा जमा होने लगा तो इन खातों में पुराने नोटे जमा करवाने पर पाबंदी लगा दी। एफडी इन्दिरा विकास पत्र आदि बचत खातों में पुराने नोटों पर पाबंदी लगा दी। ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी बैंको में पुराने नोट बदलने में रोक लगा दी। पहले कहा 30 दिसम्बर 2016 के बाद 31 मार्च 2017 तक रिर्जब बैंक में पुराने नोट जमा करवा सकते हैं लेकिन बाद में कहा कि केवल विदेशी ही करवा सकते हैं।

इस तरह पुरानी करंसी को वापिस आने से रोकेने के लिये किये गये सारे प्रयास असफल हो गये। क्योंकि आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकद करंसी के रूप में कालाधन केवल 5 से 6 प्रतिशत ही रहता है। सरकार का इस तरह सारा आंकलन फेल हो गया और 99% पुरानी करंसी उसके पास वापिस आ गयी । लेकिन बड़े घरानो का कर्ज वापिस नही आया अब बैंको को संकट से बचाने के लिये प्रोविजनिंग करने हेतु तथा ब्रेसल -3 के मानको को पूरा करने के लिये 5 लाख करोड़ की आवश्यकता है जिसे इस तरह से जीएसटी आदि के माध्यम से पूरा करने की योजना पर काम किया जा रहा है फिर सरकार ने स्मार्ट सिटी, मेक-इन-इण्डिया, डिजिटल इन्डिया और स्टॉट अप जैसी जितनी भी विकास योजनाएं घोषित की हैं वह सब विदेशी कर्जे पर आधारित हैं। लेकिन विदेशी निवेशकों ने यह निवेश करने से पहले आम आदमी को दी जाने वाली सब्सिडि आदि की सरकारी राहतों को तुरन्त बन्द करने की शर्ते रखी हैं। विदेशी निवेशक बैंको का निजिकरण चाहता है। सरकार द्वन्द में फंसी हुई है। वित्त मन्त्री ने बार-बार घोषणा की हैं कि चुनावों का वित्तिय सुधारों पर कोई असर नही पड़ेगा वह जारी रहेंगे।अब आम आदमी को सरकार के इन फैसलों का प्रभाव व्यवहार रूप में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि इसका असर इन चुनावों पर अश्वय पड़ेगा।

समर्पित आत्मा:सिस्टर निवेदिता, आज के भारत के लिए एक प्रेरणा

महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चन्द्र पाल ने कहा था, 'मुझे संदेह है कि किसी और भारतीय ने उस प्रकार भारत से प्रेम किया होगा, जैसे निवेदिता ने किया था।' टैगोर ने भारत को उनकी स्व-आहूतिपूर्ण सेवाओं के लिए उन्हें 'लोक माता' की उपाधि दी थी। सुश्री मार्गेट एलिजाबेथ नोबल को स्वामी विवेकानंद द्वारा 'समर्पित' निवेदिता का नया नाम दिया गया था।

भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामीजी के उत्कृष्ट आहवान से प्रेरित होकर निवेदिता 28 जनवरी, 1898 को अपनी 'कर्म भूमि' भारत के तटों पर पहुंची और वास्तविक भारत को जानने का कार्य आरंभ कर दिया।

अर्चना दत्ता मुखोपाध्याय

निवेदिता ने एक राष्ट्र के रूप में भारत के आंतरिक मूल्यों एवं भारतीयता के महान गुणों की खोज की। उनकी पुस्तक 'द वेब ऑफ इंडियन लाइफ' अनगिनत निबंधों, लेखों, पत्रों एवं 1899-1901 के बीच एवं 1908 में विदेशों में दिए गए उनके व्याख्यानों का एक संकलन है। ये सभी भारत के बारे में उनके ज्ञान की गहराई के प्रमाण हैं।

भारतीय मूल्यों एवं परम्पराओं की महान समर्थक निवेदिता ने 'वास्तविक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा' के ध्येय को आगे बढ़ाया और उनकी आकांक्षा थी कि भारतीयों को 'भारत वर्ष के पुत्रें एवं पुत्रियों' के रूप में न कि 'यूरोप के भद्दे रूपों' में रूपांतरित किया जाए। वे चाहती थीं कि भारतीय महिलाएं कभी भी पश्चिमी ज्ञान और सामाजिक आक्रामकता के मोह में न फंसे और 'अपने वर्षो पुराने लालित्य एवं मधुरता, विनम्रता और धर्म निष्ठा' का परित्याग न करें। उनका विश्वास था कि भारत के लोगों को 'भारतीय समस्या के समाधान के लिए' एक 'भारतीय मस्तिष्क' के रूप में शिक्षा प्रदान की जाए।

निवेदिता ने 1898 में कोलकाता के उत्तरी हिस्से में एक पारम्परिक स्थान पर अपना प्रायोगिक विद्यालय खोला न कि नगर के मध्य हिस्से में जहां अधिकतर यूरोप वासी रहते थे। उन्हें वास्तव में अपने पड़ोस के हर दरवाजे पर जाकर छात्रों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विद्यालय आधुनिक युग की 'मैत्रेयी' और 'गार्गी' का निर्माण करें और इसे एक 'महान शैक्षणिक आंदोलन' का केन्द्र बिन्दु बनाए।

विद्यालय की गतिविधियां सच्चे राष्ट्रवादी उत्साह में डूबी हुई थीं। जब देश में 'वन्दे मातरम' पर प्रतिबद्ध लगा हुआ था, उस वक्त यह प्रार्थना उनके विद्यालय में गाई जाती थी। जेलों से स्वतंत्रता सैनानियों की रिहाई उनके लिए जश्न का एक अवसर हुआ करता था। निवेदिता अपने वरिष्ठ छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के महान भाषणों को सुनने के लिए ले जाया करती थीं जिससे उनमें स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को पिरोया जा सके।

1904 में निवेदिता ने महान संत 'दधीचि' स्व आहुति के आदर्शो पर केन्द्र में 'व्रज' के साथ पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की एक प्रतिकृति की

डिजाइन बनाई थी। उनके छात्रों ने बंगला भाषा में 'वंदे मातरम' शब्दों की कशीदाकारी की थी। इस ध्वज को 1906 में भारतीय कांग्रेस द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में भी किया गया था।

उनके लिए शिक्षा सशक्तिकरण का एक माध्यम थी। निवेदिता ने अपने छात्रों को उनके घरों से आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ हस्तकलाओं एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण भी दिया। वह वयस्क एवं युवा विधवाओं को शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में लेकर आई। निवेदिता ने अपने दिमाग में पुराने भारतीय उद्योगों के पुरुत्थान एवं उद्योग तथा शिक्षा के बीच संपर्क स्थापित करने की एक छवि बना रखी थी।

निवेदिता ने भारतीय मस्तिष्कों में राष्ट्रवाद प्रज्ज्वलित करने में महान भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के पुरुषों एवं महिलाओं से अपील की कि वे अपनी मातृभूमि से प्रेम करने को अपना नैतिक कर्तव्य बनाए, देश के हितों की रक्षा करना अपनी 'जिम्मेदारी' समझें और मातृभूमि की पुकार पर किसी भी आहूति के लिए तैयार रहें।

भारत का एकीकरण उनके दिमाग में सबसे ऊपर था और उन्होंने भारत के लोगों से अपने दिल एवं दिमाग में इस 'मंत्र' का उच्चारण करने का आग्रह किया कि 'भारत एक है, देश एक है और हमेशा एक बना रहेगा।'

निवेदिता ने 1905 में पूरे मनोयोग से स्वदेशी आंदोलन का स्वागत किया और कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था का मसला ही नहीं है बल्कि यह भारतीयों के लिए एक 'तपस्या' भी है।

निवेदिता विभिन्न विषयों पर एक सफल लेखिका थीं। ज्वलंत मुद्दों पर भारत के दैनिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपे उनके लेख लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते थे और उन्हें कदम उठाने के लिए प्रेरित करते थे, चाहे यह स्वतंत्रता आंदोलन हो, कला एवं संस्कृति का उत्थान हो या आधुनिक विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना हो।

निर्धनों एवं जरूरतमदों के प्रति निवेदिता की सेवाएं, चाहे कोलकाता में प्लेग महामारी के दौरान हो या बंगाल में बाढ़ के दौरान, उनके बारे में बहुत कुछ कहती हैं। निवेदिता भारत में किसी भी प्रगतिशील आंदोलन में एक उल्लेखनीय ताकत बन गई।

वास्तव में उनकी 150वीं जयंती मनाने के इस अवसर पर राष्ट्र को उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के योगदान का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। निवेदिता ने भारत में महिलाओं के लिए 'प्रभावी शिक्षा' एवं 'वास्तविक मुक्ति' को 'कार्य करना, तकलीफें झेलना और उच्चतर स्थितियों में प्रेम करना, सीमाओं से आगे निकल जाना, महान प्रयोजनों के प्रति संवेदनशील रहना, राष्ट्रीय न्यायपरायणता द्वारा रूपांतरित होना, के रूप में परिभाषित किया है। यह आज के भारत में महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो जीवन के कठिन कार्यक्षेत्र में सामाजिक पूर्वाग्रहों, वर्जनाओं एवं सांकृतिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ते हुए अपने कौशलों को प्रखर बना रही हैं।

भारतीय गौरवशाली गणराज्य के रचयिता सरदार पटेल

स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को परिणति तक पहुंचने के ऐन पहले पांच सौ से ज्यादा देसी रियासतों में बंटे भारत वर्ष को एकसूत्र में पिरोकर भारत संघ में शामिल करना एक असंभव काम था। इसके लिए रियासतों को राजी करना, फिर आजादी के साथ ही मिले विभाजन के बेहद खुरदरे जख्म पर मखमली मरहम लगाना, ये सारे काम सबल राष्ट्र की मजबूत नींव के लिए जरुरी था। इन शुरुआती दुरुह कामों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी सरदार बल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल ने अपने कंधे पर ली। उनके अथक और अहिर्निश मेहनत का नतीजा है कि आज भारतीय गणतंत्र की दुनिया भर में तूती बोल रही है। यह हमारा सौभाग्य था कि सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। गृह मंत्रालय का प्रभार उनके पास रहा। फिर उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद का जबरदस्त इस्तेमाल किया। लौहपुरुष के तौर पर बनी उनकी कूटनीति छवि पीढ़ियों के प्रेरक बनी रहेंगी अपने इस महानायक की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र ने आजादी के सडसठ साल बाद 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। राष्ट्रीय एकता में एतिहासिक योगदान करने वाले नायक सरदार पटेल की नर्मदा डैम पर 182 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। इसके लिए देशभर से लोहे मंगवाकर एकता का अतुलनीय मिसाल पेश की गई है।

''आलोक कुमार''

स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को परिणति तक पहुंचने के ऐन पहले पांच सौ से ज्यादा देसी रियासतों में बंटे भारत वर्ष को एकसूत्र में पिरोकर भारत संघ में शामिल करना एक असंभव काम था। इसके लिए रियासतों को राजी करना, फिर आजादी के साथ ही मिले विभाजन के बेहद खुरदरे जख्म पर मखमली मरहम लगाना, ये सारे काम सबल राष्ट्र की मजबूत नींव के लिए जरुरी था। इन शुरुआती दुरुह कामों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी सरदार बल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल ने अपने कंधे पर ली। उनके अथक और अहिर्निश मेहनत का नतीजा है कि आज भारतीय गणतंत्र की दुनिया भर में तूती बोल रही है। यह हमारा सौभाग्य था कि सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। गृह मंत्रालय का प्रभार उनके पास रहा। फिर उन्होंने (साम, दाम, दंड, भेद) का जबरदस्त इस्तेमाल किया। लौहपुरुष के तौर पर बनी उनकी कूटनीति छवि पीढियों के प्रेरक बनी रहेंगी अपने इस महानायक की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र ने आजादी के सडसठ साल बाद 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। राष्ट्रीय एकता में एतिहासिक योगदान करने वाले नायक सरदार पटेल की नर्मदा डैम पर 182 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। इसके लिए देशभर से लोहे मंगवाकर एकता का अतुलनीय मिसाल पेश की गई है।

बीते तीन वर्षों की तरह ही इस बार भी 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार का 'राष्ट्रीय एकता दिवस' पर महानायक सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विशेष आयोजनों पर जोर है। ताकि भावी पीढी को राष्ट्रनायक के कृतत्व से परिचित कराया जा सके। भारत सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल के अप्रतीम योगदान और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के उनके बेजोड़ काम को याद किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों की सफलता के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें राष्ट्रीय एकता के मौके पर 'एकता के संकल्प' को सुदृढ करने वाले कार्यक्रमों की सफलता में विशेष योगदान करने का आग्रह किया गया

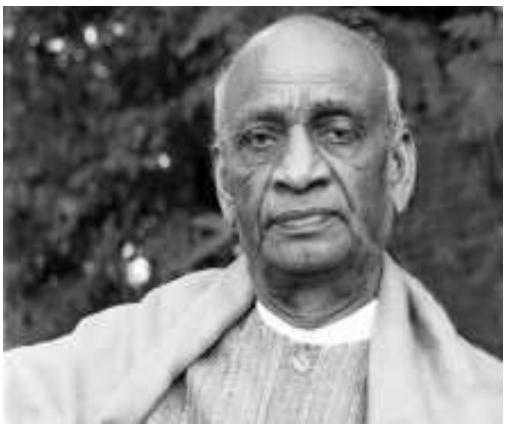

है। राष्ट्रीय एकता के संकल्प को सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रम की एतिहासिक सफलता के लिए विभिन्न शासकीय मुख्यालयों पर अर्द्धसैनिक बलों का मार्च पास्ट, एकता दौड़, पोस्टर व क्विज प्रतियोगिताएं, सरदार पटेल के योगदान के रेखांकित करने वाली प्रदर्शनियों के आयोजन किए जा रहे है। स्कूल-कालेजों में इस अवसर पर विशेष आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वंय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्रीय एकता दिवस की सफलता के प्रति विशेष आग्रह है। इस बार 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग स्थित सरदार पटेल चौक पर सरदार की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एकता के लिए यूनिटी रन को प्रधानमंत्री हरी झंडा दिखाएंगे। इसमें लगभग 15,000 छात्र, पूर्व सैनिक, प्रसिद्ध एथलीट और एनएसएस स्वयसेवकों को भाग लेना है। इस फ्लैग-ऑफ में एमएसपी वी सिंधु (बैडमिंटन), एमएस मिताली राज (क्रिकेट) और सरदार सिंह (हॉकी) सहित खेलकूद के कई शीर्षस्थ खिलाडी मौजूद रहेंगे।

इसके अलावा रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, सूचना और प्रसारण और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों समेत केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों को एकजुटता के संदेश को फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही हैं। कनॉट प्लेस के केंद्रीय पार्क और चाणक्यपुरी में शांति पथ पर रोज गार्डन में सरदार पटेल क याद में प्रदर्शनी का आयोजन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस को एक त्योहार का रंग देने की तैयारी कर रखी है। रेडियो व दूरदर्शन पर सरदार पटेल पर आधारित कार्यक्रमों का बोलबाला रहेगा। सरदार पटेल पर छह पुस्तकों के नए संस्करण जारी किए जाएंगे और वे ई-पुस्तक के रूप में उपलब्ध होंगे।

महानायक सरदार पटेल के योगदान के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वह आजादी का संक्रमण काल में ही राष्ट्र निर्माण के प्रति सक्रिय हो गए थे। रियासतों में बिखरे पडे राष्ट्र को समेटने के लिए सरदार पटेल ने अथक काम किया। उन्होंने भारत के तत्कालीन गृह मंत्री के तौर पर उन स्वंय संप्रभुता वाले रियासतों का भारतीय संघ में विलय आरंभ कर दिया जो अलग पहचान रखती थीं। उनका अलग झंडा और शासक था। देसी रियासतों को एक करने का असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को उन्होने विस्मित करने के अंदाज में पूरा किया। इससे दुनिया ने भारत की कूटनीति का लोहा मान लिया। बल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली में अंग्रेजों के खिलाफ सफल किसान आंदोलन किया था। तब वहां की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। बाद में अपनी शासकीय क्षमता और अतुल्य कूटनीतिक क्षमता की वजह से सरदार पटेल को 'लौहपुरुष' कहा जाने लगा। लौहपुरुष पटेल ने राष्ट्र निर्माण के लिए चाणक्य सा कौशल और अप्रतीम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया।

उन्होने भावी भारत के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासतों के प्रति रीति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, 'रियासतों को तीन विषयों- सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा।' यह एलान काम कर गया। इसके साथ ही देसी रियासतों के संघ में बिखराव की प्रक्रिया शुरु हो गई। धीरे धीरे बहुत सी देसी रियासतों के शासक भोपाल के नवाब से अलग हो गए। इससे नवस्थापित रियासती विभाग की योजना को सफलता का आधार मिला। यह इतिहास में भारतीय कूटनीति के लिए गर्व का हिस्सा है कि अहिर्निश मेहनत करते सरदार पटेल ज्यादातर देसी राजाओं को समझाने में सफल रहे कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरुप तीन को छोड़कर सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ, तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया। सरदार पटेल की सदारत में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। कूटनीति की असली परीक्षा हैदराबाद के निज़ाम ने ली। जब उसने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात के एक लेवा कृषक परिवार में हुआ था। छोटे से गांव में पैदा हुए सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कडी करके मेहनत से इतना पैसा बचाया कि वह उच्च कानूनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड जा पाएं। पढाई पूरी कर वापस अहमदाबाद आ गए और अपनी कानूनी क्षमता से आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। फिर महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।

महात्मा गांधी ने अपने सफल सिपाही सरदार पटेल को लिखा, 'रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे।' निस्संदेह एक रक्तहीन क्रांति से 562 रियासतों का एकीकरण दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। आजादी के बाद बनी सरकार में विदेश विभाग प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के पास था। उप प्रधानमंत्री के नाते सरदार पटेल कैबिनेट की विदेश विभाग की समिति में जाते थे। उन बैठकों में पंडित नेहरु से उनका खटपट होना बताता है कि उनकी दूरदर्शिता का लाभ लिया गया होता तो वतर्मान में मौजूद अनेक समस्याओं का जन्म नहीं होता। मसलन 1950 में पटेल ने पंडित नेहरु को खत लिखकर चीन तथा उसकी तिब्बत नीति के प्रति आगाह किया था। चीन के कपटपूर्ण और विश्वासघाती रवैए का जिक्र किया था। तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर कहा था कि इससे नई समस्याएं जन्म लेंगी। 1950 में नेपाल के संदर्भ में सरदार पटेल के लिखे पत्र से भी पंडित नेहरु सहमत नहीं थे। इसी तरह गोवा को आजादी दिलाने में 1950 में ही योगदान के प्रति पटेल ने उत्सुकता दिखाई थी। गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में दो घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में सरदार पटेल ने कहा, ह्क्या हम गोवा जाएंगे? दो घंटे की बात है।' उससे नेहरु बड़े नाराज हुए थे।

प्रशासनिक कौशल का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने नौकरशाही के सुधार पर काम किया। अंग्रेजों को सेवा देने की वजह से राजभक्ति के लिए बनी भारतीय नागरिक सेवा (आईसीएस) का भारतीयकरण किया। राजभक्ति की जगह देशभक्ति को तव्वजो देते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) बनाया। राष्ट्र निर्माण के वक्त वह पाकिस्तान के छल व चालाक चालों के प्रति सतर्क रहे। सरदार पटेल उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने भारतीय गणराज्य को एक शानदार इतिहास दिया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 'राष्ट्रीय एकता दिवस' जैसे के सफल आयोजनों के जरिए लोग प्रेरित होंगे। भावी पीढ़ियां भारत को फिर से ज्ञान, कौशल व प्रतिभा से विश्व विजयी बनाने में लगी रहेंगी।

पसूका

वामपंथियों की दहलीज पर हर्ष महाजन व प्रतिभा सिंह

अर्की/शैल। अपने पति मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जीत की खातिर उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके सबसे वफादार सिपहसलार हर्ष महाजन अर्की में वामपंथियों की दहलीज पर जा पहुचे हैं। हर्ष महाजन ने वामपंथियों से बैठक की व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए समर्थन मांगा। अर्की में वामपंथियों का 10-15 हजार जैसा बड़ा वोट बैंक तो नहीं हैं। लेकिन बाजी पलटने के लिए काफी है।

जानकारी के मुताबिक बीते दिनों मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अर्की चुनावी हलके में वामपंथियों के वोट लेने के लिए उनसे संपर्क किया। लेकिन इस बावत वामपंथियों ने कोई तरजीह नहीं दी। लेकिन आज मुख्यमंत्री के वफादार हर्ष महाजन वामपंथियों की दहलीज पर गए थे। ये अप्रत्याशित था। इस मौके पर वामपंथियों ने हर्ष महाजन की क्लास लगाई व स्थानीय लोगों पर वीरभद्र सिंह सरकार की ओर से किए अत्याचार याद दिलाए। माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कहा कि माकपा की बैठक चल रही थी तो इसी बीच वहां हर्ष महाजन पहुंच गए।

इस बावत अर्की के वामपंथी नेता रामकृष्ण शर्मा की अगुवाई में माकपा ने आपात बैठक बुलाई व माकपा की स्थानीय इकाई अपने फैसले से प्रदेश सचिवालय को अवगत करा देगी।

अर्की में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रचार नहीं कर रहे हैं। वहां प्रचार की कमान मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह व उनके वफादार हर्ष महाजन ने संभाली हुई हैं। वीरभद्र सिंह ने अर्की में नामाकंन का बाद पांव नहीं धरा हैं।

अर्की में भाजपा ने बिलकुल नया चेहरा मैदान में उतारा हैं व बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ग्राउंड में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन कांग्रेस हर तरह से हर वोटर तक पहुंचने के लिए कुलबुला रही है। वामपंथियों के दहलीज पर पहुंचना इसी कड़ी का हिस्सा है। ऐसे में अर्की के वामपंथी ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी वामपंथ नेतृत्व को ये फैसला लेना मुश्किल होगा कि कांग्रेस का साथ देना हैं या नहीं। वीरभद्र सिंह सरकार ने स्थानीय तौर पर ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा हैं जहां पर वामपंथियों को कुचला न हो।

उधर,इस बावत माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कहा माकपा कांग्रेस व भाजपा को कोई समर्थन नहीं देगी। इस बार वो तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी ।

देवभूमि को अपराध भूमि बनाया कांग्रेस ने:योगी

शिमला/शैल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के अर्की विधानसभा क्षेत्र के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित

करते हुये कहा कि कांग्रेस ने देव भूमि (हिमाचल प्रदेश) को अपराध भूमि में तब्दील कर दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों से माफिया राज को खत्म करने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने अर्की और हरोली में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के शासन के तहत सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार ही बढ़ा है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने योगी को पार्टी का मुख्य प्रचारक बनाया है। राज्य में नौ नवंबर को मतदान होना है।

मोदी ने व्यापारियों को खून के आंसू पीने पर किया मजबूर:आनंद शर्मा

शिमला/शैल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर प्रवक्ता एवं अमृतसर से विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर शिमला के

मॉल रोड में एक रोड शो तथा डोर टू डोर चुनाव प्रचार कांग्रेस उम्मीदवार हरभजन सिंह भज्जी के हक में किया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आनंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।

डाक्टर वेरका ने कहा कि अभी अभी पंजाब की जनता ने गुरदासपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को दिन में तारे दिखा दिए और अब हिमाचल प्रदेश की जनता भी ये ही करेगी। आनद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हितों की आवाज बनी है और भाजपा के मोदी ने भारत के व्यापारियों को आम जनता को खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया है। डॉक्टर वेरका ने कहा कि जैसे गुरदासपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक जुट होकर चुनाव लड़ी थी उसी तरह यहाँ भी चुनाव लड़ा जायेगा। इस मौके पर डॉक्टर वेरका के साथ उनके राजनितिक सलाहकार अमन शर्मा, मीडिया सलाहकार विकास दत्त, गौरव शर्मा विशेष रूप से मौजूद थे।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पस्त मुख्यमंत्री फर्जी आँकड़ो की जादूगरी में व्यस्त:अनुराग ठाकुर

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कुटलैहड़ में जनसभा को सम्बोधित करते हुए राज्य में गिरती शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा में गुणवत्ता के आभाव में राज्य के छात्रों का दूसरे

राज्यों की तरफ पलायन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बजाए लगातार झूठ बोलने पर इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। जनसभा के दौरान विश्वविख्यात गायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता पद्मश्री हंसराज हंस ने भी लोगों को सम्बोधित किया और पूर्ववर्ती धूमल सरकार के जनहित कार्यों को याद किया।

राज्य में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'राज्य में शिक्षा व्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो चुकी है जिन स्कूलों में छात्र हैं अध्यापक नहीं और जहां अध्यापक हैं वहाँ छात्र नहीं। आलम ये है कि 7वीं क्लास का बच्चा तीसरी क्लास का इम्तिहान पास नहीं कर पा रहा है लोगों को मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करना पड़ रहा है। राज्य में गुणात्मक शिक्षा के आभाव में छात्रों को पढ़ाई खत्म करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, और तो और मुख्यमंत्री ने इन बेरोजगार छात्रें का भी बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जमकर शोषण किया और बेरोजगारी भत्ता देने के फर्जी आँकड़े देकर इनका मजाक बनाया है।

प्राथमिक शिक्षा के मुद्दे पर ठाकुर ने कहा 'हिमाचल में करीब 10766 प्राथमिक स्कूल हैं इनमें से लगभग 200 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं हैं, 100 विद्यालयों में एक या दो छात्र हैं, और 923 विद्यालय तो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 2003-04 में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय का नामांकन 89% था और निजी विद्यालयों में सिर्फ 11%, लेकिन 2015-16 में यह सरकारी स्कूलों में 55% से नीचे आ गया था और निजी स्कूल में 45% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 2012 का समय तय किया गया था और शिक्षा की गुणवत्ता पूरी करने के लिए 2015 की समय सीमा तय थी। इसके बावजूद स्कूलों में न तो आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

उच्च शिक्षा में मसले पर हमीरपुर सांसद ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए खुले कई संस्थानो पर राज्य सरकार की नीतियों के चलते कइयों पर ताले लटकने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग तक की शिक्षा की हालत खराब है। सरकारी इंजीनियरिंग, मेडिकल और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की भारी कमी के चलते प्रदेश में निजी गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान कुकरमुत्तों की तरह उग आए हैं। ये प्रदेश के नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं और जाने-अनजाने शासन-प्रशासन उसका भागीदार है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी के चलते छात्रों को राज्य के बाहर का रूख करना पड़ रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर हर मुद्दों पर झूठ बोलने और झूठ उजागर हो जाने पर चुप्पी साध लेने वाली पॉलिसी अपनाए बैठे हैं।

धूमल फिर से बनेंगे प्रदेश के मुख्यमन्त्री:बलदेव शर्मा

हमीरपुर/शैल। बड़सर विधानसभा के तपा ढडवाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिला सहकारिता विकास संघ के चेयरमैन, पूर्व जिला परिषद् सदस्य यशवीर पटियाल तपा ढडवाल क्षेत्र की सात पंचायतों से सैंकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। यशवीर पटियाल कांग्रेस के जिला सचिव का कार्यभार सभाल रहे थे।

भाजपा प्रत्याशी बलदेव शर्मा की अगुवाई में सैंकड़ों लोग समीरपुर पहुंचे। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वालों में बड़सर कांग्रेस के सचिव रहे एवं करेर पंचायत प्रधान सुदर्शन शर्मा के भाई सुरेश शर्मा सहित समैला, महारल, सकरोह, घोड़ी/बिरी, बड़ाग्राम, करेर और मोर्सू सुल्तानी पंचायत से कांग्रेस के कई अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी का पटका पहना कर इनका स्वागत किया।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा की निश्चित तौर पर कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उसको छोड़ कर लोग भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा देश और प्रदेश का भविष्य है, सभी समझदार लोग भाजपा परिवार में आ रहे हैं, सबको मान सम्मान मिलेगा, भाजपा मजबूत होगी। और उनके सहयोग से हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। फिफ्टी प्लस अब सिक्सटी प्लस होकर रहेगा। हिमाचल निर्माता वाई एस परमार के परिवार के लोग और वीरभद्र सिंह के ससुराल के लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं। खुद कांग्रेस के परिवार के लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। भाजपा की नीतियों और मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कांग्रेस के मंत्री भी भाजपा में शामिल हुए हैं। सब जानते हैं कि जब मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रम्प जीत सकते हैं तब हिमाचल में भी भाजपा जीतेगी।

पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा की प्रो. धूमल के करिश्माई नेतृत्व से प्रभावित होकर हजारों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं और जहां तक पांच साल की बात है बड़सर विस में कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। विकास केवल विधायक और उसके चहेतों का हुआ है। इसीलिए कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, अभी और भी होंगे, उनका स्वागत है। उन्होंने दावा किया प्रो. धूमल फिर से सरकार बनाकर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बनेंगे।

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए यशवीर पटियाल ने कहा की कांग्रेस में हुए अपमान के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था। जबकि भाजपा का नाम ही विकास है, भाजपा सम्मान देती है, और प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने जो नायाब नेतृत्व इस प्रदेश को दिया है, जिला हमीरपुर में जो विकास करवाया है उसको देखते हुए हम उनकी शरण में आये हैं।

16 मतदान केंद्रों का संचालन करेंगी महिला अधिकारी व कर्मचारी

शिमला/शैल। जिला शिमला में 16 मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया के संचालन का पूर्ण दायित्व महिलाएं संभालेंगी। हर विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो ऐसे मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर मतदान केंद्र के सभी दायित्वों का निर्वहन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इन मतदान केंद्रों में सभी मतदान अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला की यह एक अनूठी पहल है।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अधिमान देने के लिए जिला प्रशासन शिमला द्वारा कई महत्वकांक्षी प्रयास किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान इन प्रयासों को और अधिक महत्व देने के लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि जिला में सभी विधान सभा क्षेत्रों में दो ऐसे मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां मतदान की सारी प्रक्रिया का संचालन महिला अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि महिलाएं भय मुक्त होकर अपने अधिकारों को जानें तथा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, इसी बात को ध्यान में रखकर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों आधारित मतदान केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह मतदान केंद्र महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण होंगे।

महिलाएं हमारे समाज की प्रगति और उन्नति में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानि निर्वाचन में भी महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह के मतदान केंद्रों की स्थापना निर्वाचन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

इन महिलाओं को निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में बचत भवन शिमला में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शिमला, शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी के महिला अधिकारियों व महिला कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें ईवीएम और वीवीपैट मशीन के संचालन, उनके रखरखाव और प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलु की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

हिमाचल में हैं 13,677 दिव्यांग मतदाता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रदेश के कुल 13,677 दिव्यांग मतदाता हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कुल 13,677 दिव्यांग मतदाताओं में से 8,555 विशेष रूप से सक्षम, 1,844 दृष्टिबाधित, 1,388 मूकबधिर और 1,890 अन्य दिव्यांग सम्मिलित हैं। इन मतदाताओं को संबंधित मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर के माध्यम से ले जाने के लिए रेम्प, ब्रेल वोटर स्लिप, मतदान के लिए सहयोगी और जहां संभव हो, वहां वाहन की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल वोटर स्लिप के जरिए मतदान कर सकेंगे। ब्रेल के माध्यम से वे अपने प्रत्याशी का चयन कर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसी तरह, विशेष तौर पर सक्षम, मूकबधिर और अन्य दिव्यांगों के लिए संबन्धित बूथों पर व्हील चेयर ले जाने के लिए रेम्प, सहयोग के लिए सहयोगी और जहां संभव हो वहां वाहन की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि मण्डी जिले में सबसे अधिक 4,868 दिव्यांग हैं जबकि लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 68 दिव्यांग मतदाता हैं।

निर्वाचन नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करें :उप निर्वाचन आयुक्त

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सेना ने शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिला के जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक

कर विधानसभा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया।

सक्सेना ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उप निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा लिया और उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम समयबद्ध उठाए जाएं। उन्होंने वीवीपैट मशीन के संचालन व प्रयोग के बारे में अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ आम लोगों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के समीप मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों और मत प्रतिशतता भी बढ़े।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार-संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए सभी कदम समयबद्ध उठाए जाएं।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान धन, बल व शराब के दुरूपयोग को रोकने के लिए कदम सख्ती से उठाए जाएं, साथ ही उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में सचिव भारत निर्वाचन आयोग राहुल शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश पुष्पेंद्र राजपूत और विभिन्न जिलों में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे।

सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने पर पाबंदी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र राजपूत ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सार्वजनिक परिसर की दीवारों पर लिखने, पोस्टर अथवा पेपर लगाने, किसी भी प्रकार से सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, कटआउट, होर्डिंग, बैनर तथा झण्डे इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राजपूत ने कहा कि यदि स्थानीय कानून किसी सार्वजनिक स्थान की दीवार पर नारा लेखन, पोस्टर इत्यादि लगाना अथवा कटआउट, होर्डिंग, बैनर या राजनीतिक विज्ञापन लगाने की अनुमति, भुगतान या अन्य किसी आधार पर देता है तो ऐसा न्यायालय के आदेशों एवं कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित बनाना होगा कि ऐसा स्थान किसी विशेष दल अथवा उम्मीदवार के आधिपत्य में न रहे। इस संबंध में सभी दलों और उम्मीदवारों को बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि स्थानीय कानून निजी सम्पत्ति की दीवारों पर लिखने, पोस्टर चिपकाने अथवा ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देते जिससे सम्पत्ति खराब होती हो और जिसे हटाया न जा सके, तो इसकी अनुमति सम्पत्ति के मालिक की सहमति के बाद भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंट, कार्यकर्ता और सहयोगी अपने परिसर में चुनाव चिन्ह दर्शाता एक झण्डा लगा सकते हैं। किन्तु ऐसा वे अपनी इच्छा से और किसी भी दल, संस्था और व्यक्ति के दबाव के बिना करेंगे। ऐसा करने से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी निजी सम्पत्ति पर राजनीतिक विज्ञापन दर्शाता कोई भी होर्डिंग, बैनर अथवा कटआउट नहीं लगाया जा सकेगा।

राजपूत ने कहा कि स्थानीय कानून के अनुसार यदि उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि लगाएंगे तो ऐसे में उन्हें सम्पत्ति के मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त कर इसकी प्रति निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी। विशेष अभियान पर किया गया खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उम्मीदवार ऐसी सूचना ग्राम/इलाका/शहर के अनुसार निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को अनुमति मिलने के तीन के भीतर उपलब्ध करवाएंगे ताकि चुनाव से संबंधित कोई भी अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक इसकी आसानी से जांच कर सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल/संस्था/उम्मीदवार/व्यक्ति स्थानीय कानून अथवा उपरोक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना कर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दोषी को नोटिस जारी कर सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को हटाने के लिए कहेगा। यदि इस दिशा में उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो अधिकारी इन पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंग इत्यादि को स्वयं हटाएंगे और इसका खर्चा दोषी राजनीतिक दल/संस्था/उम्मीदवार/व्यक्ति से वसूला जाएगा और यह खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। दोषी के विरूद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यावसायिक वाहन किसी भी प्रकार का झण्डा अथवा स्टीकर तभी प्रयोग कर सकता है जब यह वाहन वैध रूप से चुनाव अभियान में प्रयोग में लाया जा रहा हो और इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई हो। यह अनुमति वाहन के अगले शीशे पर दर्शानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जिन वाहनों में बदलाव किया गया है अथवा विशेष अभियान के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले वीडियो रथ वाहन इत्यादि का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकता है।

भाजपा ने बागीयों को किया निष्कासित

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने तथा पार्टी विरोधी कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरन्त प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें ललित ठाकुर भरमौर, बी0के0 चौहान, चम्बा, डी0के0 सोनी चम्बा, बलदेव ठाकुर, फतेहपुर, प्रवीण शर्मा, पालमपुर, हॅस राज धीमान, जसवां प्रागपुर,हृदय राम, रेणुका हैं।

निर्वाचन विभाग को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की 22 शिकायतें मिली

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग को 12 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से आठ राजनीतिक दलों जबकि चार आम जनता के माध्यम से मिली है। विभाग को अब तक कुल 89 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 16 का निपटारा कर लिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि स्टेटिक दल द्वारा 6 लाख 20 हजार 560 रुपये तथा पुलिस के दस्तों द्वारा 7 लाख 29 हजार रुपये की धनराशि पकड़ी जा चुकी है। निर्वाचन विभाग के पास आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 22 शिकायतें प्राप्त हुई है। विभाग के पास अब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 59 का निपटारा कर लिया गया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भाजपा के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के दावे पर सुखराम की सजा का ग्रहण

शिमला/शैल। भाजपा ने प्रदेश में अपने चुनाव की शुरूआत 'हिसाब मांगे हिमाचल' के नाम से एक पत्र जारी करके की थी। यह पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह के काग्रेस दौरे से पहले जारी किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. संबित पात्रा की प्रैस वार्ता में जारी किये इस पत्र में वीरभद्र सरकार को माफिया सरकार करार दिया गया था। यह पत्र जारी होने के बाद भाजपा की हर पत्रकार वार्ता में प्रदेश के सुसाशन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया जा रहा है। क्योंकि पार्टी ने अपने अभियान की शुरूआत ही 'हिसाब मांगे हिमाचल' से की है। लेकिन जब यह पत्र जारी किया गया था उस समय प. सुखराम का परिवार भाजपा में शामिल नही हुआ था। परन्तु आज न केवल यह परिवार भाजपा में शामिल ही हो चुका है बल्कि उनके मन्त्री बेटे अनिल को मण्डी से पार्टी का टिकट भी दे दिया गया है। सुखराम को संचार घोटाले में सजा हो चुकी है और वह सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ती उम्र और बीमारी के आधार पर अन्तरिम ज़मानत पर है। अनिल शर्मा पर भाजपा अपने ही आरोप पत्रों में गंभीर आरोप लगा चुकी है।

इस पृष्ठभूमि में जब भाजपा वीरभद्र और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है तब उसके आरोपों की गंभीरता स्वयं ही सवालों में आ खड़ी होती है। भाजपा जब वीरभद्र और उनके परिवार पर ज़मानत पर होने का आरोप लगाती है तब उससे सुखराम को लेकर सवाल पूछे जाने स्वभाविक है। लेकिन इन सवालों का कोई जवाब भाजपा नही दे पा रही है। बल्कि तब उसके सामने यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अपने जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं वह सब भी ज़मानत पर है। इनमें सांसद विरेन्द्र कश्यप का केस ऑन कैमरा विधायक राजीव बिन्दल का सोलन नगर पालिका का प्रकरण तथा एचपीसीए को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चल रहे मामले चर्चा में आ जाते हैं। जो स्थिति इन आपराधिक मामलों में भाजपा नेताओं की है, वही स्थिति वीरभद्र और उनके परिवार की उनके मामलों में है। क्योंकि वीरभद्र को अभी तक किसी भी मामलें में कोई सजा नही हुई है। बल्कि अभी ईडी का मामला तो अदालत में पहुंचा ही नही है।

इसी परिदृश्य में जब भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा करती है तब उसके दावे उसी के द्वारा सौंपे गये आरोप पत्रों पर अपनी सरकार आने पर आज तक कोई कारवाई न करने का कड़वा सच उसके सामने आ खड़ा होता है। भाजपा ने चिट्टो पर भर्ती मामले में दो-दो जांच कमेटीयां बैठाई लेकिन उनकी रिपोर्ट पर प्रदेश उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणीयों के वाबजूद कोई कारवाई नही की गई। जेपी उद्योग को 1990 में दिये गये बसपा प्रौजेक्ट के 92 करोड़ सीएजी की टिप्पणीयों के बावजूद रिकवर नही किये और अन्त में वट्टे खाते में डाले गये। जेपी के ही सीमेन्ट प्लांट में 12 करोड़ का आरोप भाजपा के आरोप पत्र में प्रमुखता से लगाया था लेकिन कोई कारवाई नही हुई। जेपी थर्मल प्लांट मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बैठायी गयी एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा नही है। बल्कि आज भाजपा ने चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा को पार्टी में शामिल करक टिकट दे देने से एक और सवाल अपनी कथनी और करनी पर खड़ा कर लिया है क्योंकि बलवीर वर्मा को नगर गिनम शिमला का 60 लाख का टैक्स चुकाना है। 90 करोड की संपति के मालिक वर्मा जब नोटिसों के बावजूद टैक्स नही चुका रहे है तो यह सवाल भाजपा पर भी आ जाता है कि वह किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने जा रही है।

यह सारे सवाल आज भाजपा के दावो के साथ उठ खड़े हुए है। क्योंकि आज भाजपा के साथ सुखराम परिवार जुड़ गया है बल्कि इसे भाजपा की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ ही भाजपा भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने और उसके खिलाफ कारवाई के दावे करने का नैतिक बल खो देती है। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि सुखराम को भाजपा में शामिल करके पार्टी अचानक ही आक्रामकता से फिसल कर रक्षात्मकता पर आ खड़ी होती है। माना जा रहा है कि भाजपा को सुखराम के ग्रहण ने जिस तरह से ग्रस लिया वह उसके लिये धातक सिद्ध होने जा रहा है।

विक्रमादित्य की संपत्ति 84 करोड़ कैसे हो गयी,भाजपा ने पूछा सवाल

शिमला/शैल। मुख्यन्त्री वीरभद्र सिंह के बेटे और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधान क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव के लिये उन्होने जो शपथ पत्र दायर किया है उसमें अपनी चल-अचल संपति 84 करोड़ दिखा रखी है। यह 84 करोड़ संपत्ति दिखाने पर भाजपा ने वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य से सवाल पूछा है कि इतनी संपत्ति पांच वर्षो में उन्होने कैसे अर्जित कर ली। फिर इसी शपथ पत्र में विक्रमादित्य ने वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से 84 लाख का कर्ज लिया भी दिखाया है। इस कर्ज पर भी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. पात्रा ने सवाल पूछा है कि जब विक्रमादित्य के पिता मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनकी माता पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के पास करोड़ो रूपया कैश- इन- हैंड था तो उन्हे यह कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। डा. पात्रा ने विक्रमादित्य और वक्कामुल्ला की कंपनीयों के व्यापारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाये हैं।

विक्रमादित्य की संपति पर यह सवाल इसलिये उठाये गये कि जब वीरभद्र सिंह ने 17.10.12 को विधानसभा चुनाव लडते हुए जो शपथ पत्र दायर किया था उसें विक्रमादित्य को अपने पर आश्रित दिखाया था। उस समय विक्रमादित्य के नाम करीब 1.5 करोड़ की संपति दिखायी गयी है। 2012 तक विक्रमादित्य कोई आयकर रिर्टन भी दायर नही करते थे। उसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी कंपनी के नाम महरौली में जो फार्म हाऊस गड्डे परिवार से 1.20 करोड में खरीदा था उसके लिये उन्हें 90 लाख वीरभद्र सिंह ने दिये थे। 30 लाख उन्होने अपने साधनों से दिये थे। लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह तीस लाख भी दो कंपनीयों से 15- 15 लाख के चैकों के माध्यम से आया है। इन कंपनीयों की वैद्धता पर भी ईडी ने सवाल उठाये हैं और इसी कारण से फार्म हाऊस की अटैचमैन्ट के आदेश हुए है।

यही नही ईडी के अटैचमैन्ट आदेश में हुए खुलासे के मुताबिक 19 नवम्बर 2011 से 25 नवम्बर के बीच वक्कामुल्ला की तीन कंपनीयों से विक्रमादित्य के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में 25.11.11 को दो करोड़ रूपये आते हैं और फिर 10.01.12. को विक्रमादित्य की कंपनी मैप्पल डैस्टीनेशन से 50 लाख वक्कामुल्ला को दे दिये जाते है। 11.1.12 को इसी कंपनी से वक्कामुल्ला की कंपनी तारिणी सुगर को 1.50 करोड़ दे दिये जाते हैं। वीरभद्र से विक्रमादित्य को 90 लाख 2.8.11 को मिलते है और विक्रमादित्य 4.8.11 को 45-45 लाख सुनीता गड्डे और पिचेश्वर गड्डे के खातों में जमा करवाते हैं। लेकिन इसके बाद नवम्बर 2011 में पहले वक्कामुल्ला दो करोड़ विक्रमादित्य को देते हैं फिर 10 जनवरी को 2012 को विक्रमादित्य की कंपनी दो करोड़ वक्कामुल्ला और उसकी कंपनी को देते हैं। संभवत: इसी लेन देन के आधार पर विक्रमादित्य और वक्कामुल्ला के रिश्तों पर सवाल उठाये जा रहे हैं। इसी कारण से विक्रमादित्य की संपति के 84 करोड़ हो जाने पर सवाल उठ रहे है।

अब गुड़िया मामले पर उठी राजनीति किसको प्रभावित करेगी

शिमला/शैल। बहुचर्चित और विवादित कोटखाई क्षेत्र के गुड़िया रेप और हत्या कांड में शिमला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये कथित अभियुक्तों के खिलाफ 90 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में चालान दायर न हो पाने के कारण इन अभियुक्तों को अदालत से ज़मानत मिल चुकी है। स्मरणीय है कि इसी कांड में गिरफ्तार हुए एक अभियुक्त सूरज की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाने पर इसी गुड़िया मामले की जांच के लिये गठित हुई पूरी एसआईटी टीम भी हिरासत में चल रही है। इस टीम की ज़मानत याचिका को अब फिर कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। स्मरणीय है कि जब यह कांड घटा था और इस पर मीडिया में चर्चा उठी थी तब इस चर्चा का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले को अपने पास ले लिया था। उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के बाद इसकी जांच के लिये सरकार ने एक एसआईजी आईजी ज़हूर जैदी की अध्यक्षता में गठित कर दी थी। लेकिन इस एसआईटी की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में रोष और अविश्वास फैल गया है। जनता ने गुड़िया को इन्साफ दिलाने के लिये एक गुड़िया न्याय मंच का गठन कर लिया। इस मंच के बैनर तले जो जनाक्रोश फूटा उससे प्रदेश दहल उठा था। बल्कि देश के कई भागों में भी इसको लेकर धरना-प्रदर्शन हुए। लोगों ने ठियोग और कोटखाई पुलिस थानों के बाहर इतना उग्र प्रदर्शन किया कि पुलिस थाने को आग तक लगा दी गयी। इस आग में थाने के मालखाने से रिकार्ड लाकर लोगों ने उसे आग की भेंट कर दिया।

जनता मे फैले जनाक्रोश का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय और सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जब सीबीआई ने यह मामला अपने हाथ में लिया तब गुड़िया के रेप और हत्या को लेकर छ: लोगों को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी थीं लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर यह आरोप लगे थे कि इसमें असली अपराधीयों को छोड़कर बेगुनाहों को पकड़ा गया है। इसी आरोप पर जनाक्रोश भड़का था और इसी बीच पुलिस कस्टडी में एक अभियुक्त की हत्या हो गयी। सीबीआई के सामने दो मामले खड़े थे। एक था गुड़िया के रेप और हत्या का मामला, दूसरा था पुलिस कस्टडी में कथित अभियुक्त सूरज की हत्या। सूरज की हत्या को एसआईटी ने अभियुक्तों के बीच हुए झगड़े का परिणाम कहा था। लेकिन जनता ने इस हत्या को भी असली अपराधियों को बचाने का प्रयास करार दिया था। सीबीआई ने भी अन्तत: इस हत्या के लिये एसआईटी टीम को जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया।

प्रदेश उच्च न्यायालय हर पखवाड़े के बाद सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर रहा है। हर बार स्टेटस रिपोर्ट दायर होने से पहले समाचार छपते रहे हैं कि सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लग गयी है, बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन हर स्टेटस रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय की नाराज़गी सामने आती रही है। गुड़िया प्रकरण में जिन लोगों को पकड़ा गया था सीबीआई उनका नार्को टैस्ट भी करवा चुकी है और इस टैस्ट के बाद भी कोई ठोस प्रमाण पकड़े गये अभियुक्तो के खिलाफ जब सीबीआई नहीं जुटा पायी तो 90 दिन के भीतर चालान दायर नही हो पाया और परिणामस्वरूप इनको ज़मानत मिल गयी।

अब सीबीआई को उच्च न्यायालय ने 30 नवम्बर तक एसआईटी के खिलाफ चालान दायर करने को कहा है और गुड़िया मामले में दिसम्बर में फिर रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिये है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ चालान दायर करने के लिये सरकार से अभियोजन की अनुमति मांग रखी है। कानून के जानकारों के मुताबिक कस्टोडियल डैथ में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नही होती है। कस्टोडियल डैथ में सीधे सवाल है कि या तो सूरज की अभियुक्तों के आपसी झगड़े में मौत हो गयी है, या फिर उसे नीयतन किसी को बचाने के लिये मारा गया है। यदि उसकी मौत आपसी झगड़े में हुई है तो उसके लिये पूरी एसआईटी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता। यदि सूरज को नीयतन किसी को बचाने के लिये मारा गया है तो यह सच्चाई बाहर आने में समय नही लगना चाहिये। लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नही आ पाया है, बल्कि अब यह सन्देह होता जा रहा है कि सीबीआई के हाथ अब तक कुछ भी ठोस नही लगा है। एसआईटी की गिरफ्तारी को भी 90 दिन होने वाले है। यदि 90 दिन के भीतर यह चालान दायर नही हो पाया तो इन लोगों को भी अदालत द्वारा ज़मानत देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह जायेगा।

गुड़िया प्रकरण से एक समय प्रदेश की राजनीति में भुचाल खड़ा हो गया था। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया था। भाजपा का हर नेता इस पर वीरभद्र सरकार को घेर रहा था लेकिन अब सीबीआई की असफलता से भाजपा के लिये इस मुद्दे का उठाना संभव नही रह गया है। बल्कि पुलिस थाना को आग लगाने और रिकार्ड जलाने के लिये जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और अब तक कारवाई नही हुई है, क्या भाजपा सत्ता में आने पर इन लोगों के खिलाफ कारवाई करेगी या नही यह सवाल अब भाजपा से पूछा जाने लगा है।